



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]  
No. 556]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2003/कार्तिक 21, 1925  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2003/KARTIKA 21, 1925

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2003

सं. 3/2003-स्वा. नियं. I

सा.का.नि. 996(अ).—फराल वर्ष 2003 2004 के लिए अफीम लाइसेंसिंग नीति के संबंध में सा.का.नि. 777(अ) दिनांक 29-9-2003 के तहत मंत्रालय की अधिसूचना का संशोधन करते हुए निम्नलिखित रूप से संशोधन किया जाए :—

2. उप-पैरा 2(ख) (iii) के पश्चात् उप-पैरा 2(ख) (iv) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए :—

‘(iv) जिन्होंने फसल वर्ष 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में 30 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर अथवा उससे अधिक और उत्तर प्रदेश में “आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त” के रूप में घोषित गांवों में 24 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर अथवा उससे अधिक की न्यूनतम उपज प्रस्तुत की है और “व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त” के रूप में घोषित गांवों में किसानों द्वारा चाहे जितनी भी अफीम की उपज प्रस्तुत की हो। तथापि, वह किसान जिन्होंने संदिग्ध अफीम प्रस्तुत की है न्यूनतम अर्हकारी उपज मानदण्ड में ढील के योग्य नहीं है। “आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त” अथवा “व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त” के रूप में किसी गांव को घोषित करने हेतु अपनाया गया मानदण्ड निम्नानुसार होगा :—

**आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त**

किसी गांव को “आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त” घोषित किया जाएगा जहां उन किसानों की संख्या, जिन्होंने विभागीय देख-रेख के अन्तर्गत अपनी अफीम पोस्त की फसल को पूर्णतया उखड़वा दिया था और उन किसानों की संख्या जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के 52 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर और उत्तर प्रदेश के लिए 46 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर की न्यूनतम अर्हकारी उपज प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उन किसानों की कुल संख्या से 30 प्रतिशत अथवा अधिक है जिन्होंने गांव में वास्तविक रूप से फसल उगाई है।

**व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त**

किसी गांव को “व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त” घोषित किया जाएगा जहां उन किसानों की संख्या जिन्होंने विभागीय देख-रेख में अपनी अफीम पोस्त की फसल को पूर्णतया उखड़वा दिया था और उन किसानों की संख्या जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए 52 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर और उत्तर प्रदेश के लिए 46 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर की न्यूनतम अर्हकारी उपज प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उन किसानों की कुल संख्या से 70 प्रतिशत अथवा अधिक है जिन्होंने गांव में वास्तविक रूप से फसल उगाई है।’

[सं. 3/2002/फा. सं. 616/3/2003-स्वा.निय.-I]

माला श्रीवास्तव, निदेशक (स्वापक नियंत्रण)

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2003

No. 3/2003-Narcotics Control-I

G.S.R. 886(E).—In modification of Ministry's Notification *vide* G.S.R. 777(E) dated 29-9-2003 regarding opium licensing policy for the crop year 2003-2004, the following modification may be made as follows :—

2. After sub-para 2(b) (iii), the sub-para 2 (b) (iv) may be inserted, as follows :—

(iv) who during the crop year 2002-2003 tendered a minimum yield of 30 kg per hectare or above in Madhya Pradesh and Rajasthan and 24 kg per hectare or above in Uttar Pradesh in villages declared as "Partially Damaged" and irrespective of the yield of opium tendered by the cultivators in villages declared as "Extensively Damaged". However, cultivators who have tendered suspect opium do not merit any relaxation in the Minimum Qualifying Yield criteria.

The criteria adopted for declaring a village as "Partially Damaged" or "Extensively Damaged" would be as follows :—

**Partially Damaged**

A village would be declared as "Partially Damaged" where the number of cultivators, who had fully uprooted their opium poppy crop under departmental supervision and the number of cultivators, who have not been able to tender the MQY of 52 kg per hectare for Madhya Pradesh and Rajasthan and 46 kg per hectare for Uttar Pradesh, is 30% or above of the total number of cultivators who have actually harvested the crop in the village.

**Extensively Damaged**

A village would be declared as "Extensively Damaged" where the number of cultivators, who had fully uprooted their opium poppy crop under departmental supervision and the number of cultivators, who have not been able to tender the MQY of 52 kg per hectare for Madhya Pradesh and Rajasthan and 46 kg per hectare for Uttar Pradesh, is 70% or above of the total number of cultivators who have actually harvested the crop in the village.

[No. 3/2002/F. No. 616/3/2003-Narcotics Control-I]

MAI A SRIVASTAVA, Director (Narcotics Control)